

सीसीई, लखनऊ

बनाम

मैसर्स विम्को लिमिटेड

5 अक्टूबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, न्या.]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985; उप-शीर्षक 4702.90/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, एस. 11 एबी/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 52-ए और 173-बी और छूट अधिसूचना नं. 89/95 दिनांक 18.5.1995:

वर्गीकरण-निर्धारिती द्वारा बेचे गए मुद्रित कागज के डिब्बों के निर्माण से अपशिष्ट/स्क्रेप/टूकड़े- के बाबत कोई घोषणा नहीं की गई- न ही वर्गीकरण सूची दाखिल की गई और न ही नियम 52ए के संदर्भ में जारी किए गए चालान डी नियम-उत्पाद शुल्क का शुल्क-कारण दिखाएँ नोटिस-राजस्व ने शुल्क की निश्चित राशि की मांग की पुष्टि की और जुर्माना भी लगाया-- - न्यायाधिकरण द्वारा अनुमत राजस्व के आदेश के खिलाफ अपील कि ऐसे अपशिष्ट/स्क्रेप/टूकड़ों पर उत्पाद शुल्क लगाना सही है।

न्यायाधिकरण तथ्यात्मक पर विचार किए बिना एक अचानक

निष्कर्ष पर पहुंचा अवधारित-इसलिए, निर्णय में निर्दिष्ट विषय पर निर्णय के आलोक में नए सिरे से विचार करने के लिए उसे प्रेषित किया गया मामला - निर्देश जारी किए गए।

उत्तरदाता- प्रत्यर्थी निर्धारिती मुद्रित पेपर बोर्ड का निर्माता है पेपर बोर्ड से बक्से। इस प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट/स्क्रेप/टूकड़ों को कथित तौर पर वर्गीकरण द्वारा बिना घोषणा किए बेच दिया गया था केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के उप-शीर्षक 4702.90 के तहत वर्गीकृत करने योग्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था। बाद में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने उत्पाद शुल्क की मांग की पुष्टि की रु. की राशि। 23,20,000/- समान राशि का जुर्माना लगाना और धारा के तहत उचित दर पर ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। 560 सी. सी. ई., लखनऊ बनाम मैसर्स विम्को लिमिटेड।

राजस्व ने तर्क दिया कि वर्गीकरण सूची दाखिल न करने का प्रभाव नियमों के नियम 173बी के तहत न्यायाधिकरण द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया है कि अपशिष्ट/स्क्रेप/टूकड़ों की बिक्री भी नहीं होती है। न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया गया; और इसके तहत छूट का लाभ अधिसूचना संख्या 89/95 दिनांकित 18.5.1995 निर्धारिती के लिए उपलब्ध नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अवधारित 1.1. केवल इसलिए कि एक शुल्क प्रविष्टि है, माल करता है जब तक निर्माण की प्रक्रिया शामिल नहीं है, तब तक यह उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हो जाता है। [पैरा 12] [566-बी]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-आई. वी. मार्कफेड वनस्पति & एलाइड इंडस्ट्रीज, (2003) 153 ई. एल. टी. 491 एस. सी. ने भरोसा किया।

1.2. चूंकि सी. ई. जी. ए. टी. ने तथ्यात्मक परिदृश्य को विस्तार से नहीं देखा है और अचानक इस निष्कर्ष पर पहुँच गया है कि कोई निर्माण शामिल नहीं है, प्रासंगिक निर्णयों के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजा जाता है। [पैरा 14] [568-ई]

कोरेस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई बनाम. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई, [2005] 1 एस. सी. सी. 385, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 4567/2002

अंतिम आदेश संख्या 247/2001-डी दिनांक 28.11.2001 से पारित किया गया सीमा शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अपील सं। ई/281/2001-डी।

नागेंद्र राय, टी. वी. रत्नम, जयेश गौरव, के. सुब्बा राव और बी. अपीलार्थी के लिए कृष्ण प्रसाद।

वी. लक्ष्मी कुमारन, आलोक यादव और राजेश कुमार उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंटा, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था।

1. इस अपील में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में सीईजीएटी) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। दिनांक 28.11.2001 के आक्षेपित निर्णय द्वारा सीईजीएटी ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि कागज और पेपर बोर्ड के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले पेपर बोर्ड के अपशिष्ट / स्क्रेप / टुकड़े कोई नई बात नहीं है, नाम, चरित्र और उपयोग में भिन्न हैं। शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए इसलिए, यह माना गया कि कोई शुल्क प्रभार्य नहीं है।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

मैसर्स विमको लिमिटेड, बरेली के खातों की जांच के दौरान, यह पता चला कि प्रतिवादी मुद्रित पेपर बोर्ड बक्से के निर्माण के लिए कागज और पेपर बोर्ड का उपयोग कर रहा था। ऐसे बक्सों के निर्माण के दौरान, अपशिष्ट/स्क्रेप/ टुकड़े उत्पन्न होते हैं, यह आरोप लगाया गया था कि यह

अपशिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (संक्षेप में टैरिफ अधिनियम) के अध्याय उप-शीर्ष 4702.90 के तहत वर्गीकृत किया गया था।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि प्रतिवादी इस अपशिष्ट/कबाड़/ टुकड़े को बेच रहा था। यह भी देखा गया कि उन्होंने अपशिष्ट/स्क्रेप/ टुकड़े के लेनदेन की घोषणा नहीं की, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में नियम) के नियम 173-बी के तहत वर्गीकरण सूची दाखिल नहीं की और निर्धारित कोई चालान जारी नहीं किया। नियम 52-ए के तहत. तदनुसार, प्रतिवादी को एक कारण बताओ नोटिस (संक्षेप में एससीएन) जारी किया गया था जिसमें यह बताने के लिए कहा गया था कि 23,20,000/- रुपये की शुल्क राशि की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए और जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए और ब्याज क्यों लगाया जाना चाहिए शुल्क नहीं लिया जाएगा. एससीएन के जवाब में, प्रतिवादी ने कहा कि स्क्रेप दो चरणों में उत्पन्न होता है; यह विनिर्माण कार्य शुरू होने से पहले उत्पन्न होता है; कि विनिर्माण-पूर्व कार्यों के दौरान उत्पन्न स्क्रेप की मात्रा पर शुल्क की मांग कायम नहीं रखी जा सकती; कि स्क्रेप विनिर्माण प्रक्रिया का परिणाम नहीं है; निर्माण शब्द का सामान्यतः अर्थ किसी नए पदार्थ को अस्तित्व में लाना समझा जाता है और इसका अर्थ केवल किसी पदार्थ में कुछ परिवर्तन उत्पन्न करना नहीं है; वह विनिर्माण परिवर्तन का

तात्पर्य है; किसी लेख में प्रत्येक परिवर्तन उपचार का परिणाम है; कि प्रत्येक उपचार विनिर्माण नहीं है क्योंकि कुछ और आवश्यक है; कि परिवर्तन होना चाहिए और एक विशिष्ट नाम, चरित्र और उपयोग वाला एक नया अलग लेख सामने आना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया कि उनके मामले में, स्क्रेप का उत्पादन विनिर्माण नहीं था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि लंबी अवधि लागू नहीं की जा सकती और मांग का बड़ा हिस्सा छह महीने की अवधि से परे था; किसी दमन या गलतबयानी का कोई सबूत नहीं था; ऐसी प्रामाणिक मान्यता थी कि माचिस की डिब्बियों के निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट शुल्क योग्य नहीं है क्योंकि यह शुल्क भुगतान वाले कागज और कार्ड बोर्ड से उत्पन्न होता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 23,20,000/- रुपये की शुल्क राशि के भुगतान की पुष्टि की और समान राशि का जुर्माना लगाया और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 11 एबी के तहत उचित दर पर ब्याज का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।).

3. सीईजीएटी के समक्ष प्रतिवादी का रुख यह था कि कोई निर्माण नहीं हुआ था क्योंकि जो कुछ भी उपयोग किया जाता है वह कागज और पेपर बोर्ड है और जो कुछ भी अपशिष्ट / स्क्रेप / पेरिंग के रूप में उत्पन्न

होता है वह झूटी भुगतान वाले कागज और पेपर बोर्ड और एक नए अलग से उत्पन्न होता है निर्माण के लिए वस्तु का एक विशिष्ट नाम, चरित्र और उपयोग होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि उनके मामले में, स्क्रेप का उत्पादन विनिर्माण नहीं था और इसलिए शुल्क योग्य नहीं था। संक्षेप में, यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि शुल्क भुगतान कागज और पेपर बोर्ड का उपयोग इसके द्वारा किया गया था, इसलिए अपशिष्ट/स्क्रेप/पेरिंग पर फिर से शुल्क की मांग नहीं की जा सकती है जो कागज और पेपर बोर्ड के अलावा और कुछ नहीं हैं।

4. यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि विभाग का रुख स्वीकार किया जाता है, तो निर्धारित मॉडवैट क्रेडिट का हकदार होगा। कागज और पेपर बोर्ड पर उपलब्ध ऐसा क्रेडिट अपशिष्ट/स्क्रेप/पेरिंग पर देय शुल्क से कहीं अधिक होगा।

5. दूसरी ओर राजस्व का रुख यह था कि जो उत्पन्न होता है वह अपशिष्ट/स्क्रेप/पेरिंग है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में इन वस्तुओं के लिए विशिष्ट शीर्षक है और इसलिए, वस्तुओं को अध्याय शीर्षक 4702.90 के तहत विशिष्ट रूप से वर्गीकृत किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्माण के परिणामस्वरूप, अपशिष्ट/स्क्रेप और पेपर बोर्ड अस्तित्व में आते हैं जो नाम, चरित्र और उपयोग में भिन्न होते हैं और इसलिए, शुल्क

योग्य होते हैं।

6. ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के अध्याय शीर्षक 4702.90 में बरामद (अपशिष्ट और स्क्रेप) कागज या पेपर बोर्ड लिखा है, और यह बरामद अपशिष्ट या स्क्रेप नहीं है। वर्तमान मामले में, माचिस की डिब्बियों के निर्माण की प्रक्रिया में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह छोटे टुकड़ों में कागज और पेपर बोर्ड होता है। इस पेपर और पेपर बोर्ड का उपयोग इनपुट के रूप में किया जाता है और जब वे अपशिष्ट/स्क्रेप/परिंग्स के रूप में दिखाई देते हैं तो वे पेपर और पेपर बोर्ड बने रहते हैं। शुल्क वसूलना एक ही उत्पाद पर दो बार शुल्क वसूलने के समान है। सीईजीएटी ने यह भी कहा कि मौजूदा मामले में कोई मूल्यवर्धन नहीं हुआ है।

7. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नियम 173 बी के तहत दायर वर्गीकरण सूची के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है और अपशिष्ट/स्क्रेप/पेरिंग की बिक्री हुई है।

8. आयुक्त ने पाया कि अधिसूचना संख्या 89/95 दिनांक 18.5.1995 के तहत छूट का लाभ उपलब्ध नहीं है।

9. निर्णायक प्राधिकारी की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया:

"मुझे लगता है कि पार्टी ने इस मामले को बिल्कुल भी गुण-दोष के आधार पर नहीं लड़ा है। पार्टी को एससीएन इस आरोप पर जारी किया गया था कि मुद्रित पेपर बोर्ड बक्से के निर्माण के दौरान अपशिष्ट पेरिंग स्क्रेप उत्पन्न होता है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (शॉर्ट टैरिफ के लिए) की अनुसूची के अध्याय उप-शीर्षक 4702.90 के तहत वर्गीकृत किया जाता है।). इस प्रकार उत्पन्न स्क्रेप केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी है यदि निर्माताओं द्वारा बाहरी खरीदारों को बेचा जाता है जो शुल्क के भुगतान पर अन्य उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माण और निपटान भी करते हैं। चूंकि पार्टी स्क्रेप अपशिष्ट पारिंग के अलावा निर्माण और स्पष्ट मिलान करती है, जिस पर शुल्क लगाया जाता है, वे अधिसूचना संख्या 89.95 दिनांक 18.5.95 के संदर्भ में शुल्क से छूट के लाभ के हकदार नहीं हैं।

इस मामले में पार्टी का यह तर्क कि इस तरह का कचरा प्री-मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न होता है, सही नहीं है। क्योंकि विनिर्माण का मतलब कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की पूरी प्रक्रिया है। यह एक बाद

का विचार है कि उन्होंने अपने कचरे और स्क्रेप को दो श्रेणियों में विभाजित किया क्योंकि उनकी 173 बी घोषणा दिनांक 28.2.1999 में माचिस की निर्माण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है जिसमें चरण- II (खाली बक्से बनाने की प्रक्रिया) प्राप्तियों से शुरू होती है। विभिन्न पेपर मिलों से जंबो रोल के रूप में कार्डबोर्ड। इसलिए इस प्रकार के स्क्रेप को निर्माण-पूर्व अपशिष्ट नहीं कहा जा सकता। विनिर्माण गतिविधि उसी क्षण शुरू हो जाती है जब कारखाना के अंदर इनपुट का प्रसंस्करण शुरू हो जाता है। पार्टी ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि तथाकथित प्री-मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग परिसर के अलावा कहीं और हुई थी।"

10. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने सीईजीएटी के आदेश का समर्थन किया।

11. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (2006 (203) ईएलटी (एस.सी.) 3) में अन्य बातों के साथ-साथ यह देखा गया:

"18. प्रश्नगत प्रविष्टि में कोई कानूनी कल्पना नहीं है।

इसमें यह नहीं कहा गया है कि धातु के एक निश्चित प्रतिशत से अधिक वाले किसी भी अवशेष को निर्मित माना जाएगा या उत्पाद शुल्क योग्य होगा। प्रतिवादी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड, जिस पर राजस्व ने भरोसा किया है, एक विपणन योग्य वस्तु के रूप में मैल की पहचान करने के लिए एक प्रासंगिक कारक हो सकता है, लेकिन फिर मैल में धातु का प्रतिशत अपने आप में इसे उत्पाद शुल्क योग्य नहीं बना सकता है, यदि यह अन्यथा नहीं है। किसी वस्तु पर सिर्फ इसलिए कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसका कुछ बिक्री योग्य मूल्य हो सकता है।

19. टैरिफ में किए गए बदलावों को देखते हुए हो सकता है कि मैल अब अपशिष्ट और स्क्रेप के विवरण का उत्तर नहीं देता है। हालाँकि, यह लगभग अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही धातु का कुछ प्रतिशत कचरे में पाया जाता है, लेकिन प्रविष्टि में कुछ और के अभाव में इसे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इंडियन एल्युमीनियम (सुप्रा) के इस न्यायालय ने वास्तव में देखा कि धातु की कुछ मात्रा मैल और स्किमिंग में पाई जाती है। हालाँकि, एक भेद किया गया था कि मैल और स्किमिंग

अपशिष्ट या स्क्रेप के समान वर्ग की धातुएँ नहीं हैं। यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि धातु का उच्च प्रतिशत होने वाला मैल एक विपणन योग्य वस्तु है, तो भी, हमारी राय में, यह सवाल उठेगा कि क्या इसे निर्मित उत्पाद कहा जा सकता है। निर्माण शब्द का तात्पर्य परिवर्तन से है। हालाँकि, प्रत्येक परिवर्तन एक निर्माण नहीं है। किसी लेख का प्रत्येक परिवर्तन उपचार, श्रम और हेरफेर का परिणाम हो सकता है। लेकिन निर्माण का अर्थ कुछ और होगा। परिवर्तन होना ही चाहिए; एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाला एक नया और अलग लेख सामने आना चाहिए। [देखें यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड एआईआर 1963 एससी 791]।"

12. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल इसलिए कि टैरिफ प्रविष्टि है, यह तब तक उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हो जाता जब तक कि इसमें विनिर्माण शामिल न हो। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-1 बनाम मार्कफेड वनस्पति और संबद्ध उद्योग [2003 (153) ईएलटी 491 (एस.सी.)] मामले में इसे इस प्रकार देखा गया:

"2. विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या "खर्च की गई पृथ्वी" पर उत्पाद शुल्क लगता है या नहीं। टैरिफ के तहत, 1985 में इसके संशोधन से पहले, यह लगातार माना जाता था कि "खर्च की गई पृथ्वी" शुल्क के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, 1985 में नए टैरिफ के लागू होने के साथ, ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों के बीच टकराव पैदा हो गया। कुछ पीठों का मानना था कि "खर्च की गई पृथ्वी" अभी भी उत्पाद शुल्क योग्य नहीं है, जबकि अन्य पीठों का मानना था कि, क्योंकि अब यह एक विशिष्ट उप-शीर्षक में शामिल हो गया है, यह उत्पाद शुल्क योग्य हो गया है। इन परस्पर विरोधी निर्णयों को देखते हुए, मामले को सीईजीएटी की बड़ी पीठ के समक्ष रखा गया, जिसने आक्षेपित निर्णय द्वारा माना कि "खर्च की गई पृथ्वी" अभी भी शुल्क योग्य नहीं थी। इसलिए ये अपीलें.

3. हमारे लिए विचार करने योग्य एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कोई वस्तु केवल इसलिए उत्पाद शुल्क योग्य हो जाती है क्योंकि वह टैरिफ मद के अंतर्गत आती है। 1985 के बाद टैरिफ आइटम 1507 में "वसायुक्त पदार्थों के उपचार से उत्पन्न अवशेष" लिखा गया है। यह प्रस्तुत किया गया

है कि "खर्च की गई पृथ्वी" उपचार के परिणामस्वरूप प्राप्त अवशेष है और इस प्रकार अब शुल्क योग्य है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि यदि कोई सामान टैरिफ प्रविष्टि के अंतर्गत आता है तो क्या "विनिर्माण और विपणन" के सुस्थापित दोहरे परीक्षण लागू होना बंद हो जाएंगे।

4. 1985 में इस प्रविष्टि के लागू होने से पहले, यह लगातार माना जाता था कि "खर्च की गई पृथ्वी" का निर्माण नहीं किया गया था। यह लगातार माना जाता रहा है कि प्रसंस्करण के बाद भी "खर्च की गई पृथ्वी" "पृथ्वी" ही बनी रहती है। यह लगातार माना जाता रहा है कि जो कुछ हुआ वह यह था कि इसकी अवशोषित करने की क्षमता कम हो गई थी। यह लगातार माना गया था कि "पृथ्वी" पर शुल्क का भुगतान किया गया है, "खर्च की गई पृथ्वी" पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा क्योंकि यह एक ही उत्पाद बना हुआ है। यह माना गया था कि "भुगतान की गई पृथ्वी" पर शुल्क लगाना दो बार शुल्क लगाने के समान होगा। इस आधार पर यह माना गया है कि "खर्च की गई पृथ्वी" उत्पाद शुल्क योग्य नहीं थी। यहां तक कि अब भी यह नहीं दिखाया गया है कि इसका निर्माण होता है।

एकमात्र निवेदन यह है कि "खर्च की गई पृथ्वी" वसायुक्त पदार्थों के उपचार के परिणामस्वरूप प्राप्त अवशेष है . निवेदन यह है कि अब एक विशिष्ट प्रविष्टि है जो "वसायुक्त पदार्थों के उपचार से उत्पन्न अवशेषों" को उत्पाद शुल्क योग्य बनाती है, "खर्च की गई पृथ्वी" पर शुल्क का भुगतान करना होगा। दूसरे शब्दों में, जो प्रस्तुत किया गया है वह केवल इसलिए है क्योंकि एक अच्छा टैरिफ मदों में से एक के अंतर्गत आता है तो यह उत्पाद शुल्क योग्य हो जाता है।

5. उनके प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, लाल वोलेन एंड सिल्क मिल्स (पी) लिमिटेड, अमृतसर बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर, चंडीगढ़, (1999 (4) एससीसी 466) के मामले पर भरोसा किया गया। इस मामले में सवाल यह था कि क्या शुल्क चुकाए गए खराब ऊनी ग्रे धागे से बने रंगे हुए खराब ऊनी धागे पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाना था। तर्क दिया गया कि कोई निर्माण नहीं हुआ। हालाँकि न्यायालय ने इस प्रकार कहा: "निश्चित रूप से "डाईड यार्न" और "ग्रे यार्न" दोनों अलग-अलग शुल्क के साथ टैरिफ आइटम के दो अलग-अलग अलग-अलग प्रमुखों

द्वारा कवर किए जाते हैं। तो यह स्वयं उन्हें अलग-अलग लेवी के साथ दो अलग-अलग सामान के रूप में पहचानता है। इस दृष्टि से यह आग्रह नहीं किया जा सकता कि “ग्रे सूत” से “रंगे सूत” का निर्माण नहीं होता है। निस्संदेह यह प्राधिकार उठाए गए विवाद का समर्थन करता प्रतीत होता है।

6. हालाँकि, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्राधिकरण में की गई टिप्पणियाँ "प्रति इनक्युरम" हैं। इस प्रकार, 1995 सप्लीमेंट (2) एससीसी 465 में रिपोर्ट किए गए कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंदौर बनाम यूनिवर्सल केबल लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के फैसले को नोट या विचार नहीं किया गया है। इस मामले में यह तर्क कि एक वस्तु उत्पाद शुल्क योग्य हो जाती है क्योंकि यह टैरिफ एंट्री के अंतर्गत आती है, को नकार दिया गया है। बी.पी.एल. के मामले में फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, (1995 सप्लीमेंट (3) एससीसी 1) यह भी माना गया है कि केवल इसलिए कि टैरिफ आइटम में बदलाव होता है, सामान उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हो जाता है। इसके बाद 13 फरवरी, 2003 को

1999 की सिविल अपील संख्या 6745 में एक निर्णय में यह माना गया कि केवल इसलिए कि कोई वस्तु टैरिफ प्रविष्टि में आती है, यह तब तक उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हो जाती जब तक कि निर्माण न हो और वस्तु विपणन योग्य न हो। लाल वूलन एंड सिल्क मिल्स मामले (सुप्रा) में यह माना गया है कि निर्माण और विपणन क्षमता का दोहरा परीक्षण लागू नहीं होना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है कि केवल इसलिए कि कोई वस्तु टैरिफ प्रविष्टि में आती है, यह माना जाना चाहिए कि उसका निर्माण हुआ है। कानून अभी भी यह बना हुआ है कि यह साबित करने का भार राजस्व पर है कि वहां विनिर्माण होता है और क्या निर्मित किया जाता है। इस मामले में यह दिखाने के लिए कोई नया सबूत नहीं रखा गया है कि निर्माण हुआ है। "खर्च की गई पृथ्वी" "पृथ्वी" थी जिस पर कर्तव्य का भुगतान किया गया है। प्रसंस्करण के बाद भी यह मिट्टी ही बना रहता है। इस प्रकार यदि इस पर दोबारा शुल्क लगाया जाता है, तो यह उसी उत्पाद पर दोहरा शुल्क लगाने के समान होगा।"

13. कोरेस इंडिया लिमिटेड, चेन्नई बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क

आयुक्त, चेन्नई (2005 (1) एससीसी 385) मामले में इस न्यायालय द्वारा क्या होता है का निपटारा किया गया है।

14. चूंकि सीईजीएटी ने तथ्यात्मक परिदृश्य पर विस्तार से विचार नहीं किया है और सहसा इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि इसमें कोई विनिर्माण शामिल नहीं है, इसलिए मामले को ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आलोक में नए सिरे से विचार करने के लिए उसके पास भेजा जाता है।

15. अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनामिका सारण (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।